

भारत में धर्मनिरपेक्षता पर एक अध्ययन

डॉ पप्पू राम कोली, व्याख्याता राजनीति विज्ञान,
राजकीय स्नातकोत्तर महा विद्यालय, प्रतापगढ़ (राजस्थान) !

सार:

यद्यपि समकालीन भारत में धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक, राजनीतिक पटल पर एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में प्रतिस्थापित हुई है लेकिन सामाजिक वैज्ञानिकों के मध्य इस अवधारणा के संदर्भ व्यापक व भन्नताएं परिलक्षित होती हैं। अतएव इसके संगोपांग एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हेतु यह आवश्यक है कि धर्मनिरपेक्षता के व भन्न आयामों का वराद ववेचन किया जाए। अतः धर्मनिरपेक्षता का एक सद्धान्त के रूप में तथा भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता से जुड़े आयामों के बारे में प्रासंगिक, समसामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द: धर्म, राजनीति, धर्मनिरपेक्षता

प्रस्तावना

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है और कैसे यह दिन-प्रतिदिन के जीवन में प्रासंगिक है इसे समझने के लिए यह इकाई धर्मनिरपेक्षता पर केन्द्रित है। समाज व भन्न संरचनाओं से बना होता है जिसमें जाति, वर्ग, लिंग, जातियता और धर्म इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्त्व हैं। इन सभी तत्त्वों में सामाजिक सामंजस्य स्थापित किए बिना समाज कार्य नहीं कर सकता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है समाज की सामाजिक संरचना के अंदर व भन्न जातियाँ, नृजातीय समूह, लिंग और धर्म भी हैं जहाँ यह सभी उपश्रेणियाँ हस्तक्षेप न करने की सामान्य समझ के द्वारा कार्य करती हैं। यही धर्मनिरपेक्षता की वस्तुतः अवधारणा है जहाँ एक निश्चित धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूहों के साथ हस्तक्षेप नहीं करता है

वर्तमान समाज में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा और इसकी प्रासंगिकता को समझने के लिए यहाँ पर हम व भन्न वैचारिक मुद्दों और उदाहरणों की चर्चा करेंगे। यह भाग धर्मनिरपेक्षता पर दार्शनिक दृष्टिकोण और समकालीन स्थिति का एक स्पष्ट वस्तुतः से विश्लेषण के साथ शुरू होता है। सबसे पहले, कुछ धार्मिक सद्धान्तों और गैर-धार्मिक दार्शनिक व्याख्याएँ धर्मनिरपेक्षता के नैतिक दर्शन को

रेखां कत या उजागर करेंगे। अगले भाग धर्मनिरपेक्षता की वस्तुतः अवधारणा और इसकी समाज में प्रासंगिकता को समझने में आपकी सहायता करेंगे।

धर्मनिरपेक्षता : अर्थ एवं परिभाषा

'सेक्युलरिज्म' (धर्मनिरपेक्षता) शब्द लैटिन भाषा के 'सेक्युलर' शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है 'वर्तमान युग या पीढ़ी'। धर्मनिरपेक्षता सामाजिक प्रगति और तार्किक व्यवहार की व्यापक समझ से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार, मानव समाज की प्रगति धर्म-निरपेक्षता की अवधारणा को आधुनिक तार्किक समाज में सामाजिक व्यवहार के स्वरूप के रूप में लायी है। यह नैतिक मतैक्य के क्षेत्र में धर्म के अधिकार को कम करने के लिए है। चर्च के प्रभुत्व से तार्किक सत्ता, जो राज्य है, को क्षेत्रों के हस्तांतरण का वर्णन करने के लिए धर्मनिरपेक्षता एक अवधारणा के रूप में सर्वप्रथम यूरोप में अस्तित्व में आयी। वैधानिक तार्किक सत्ता या राज्य को एक गैर-धार्मिक या तटस्थ सत्ता माना जाता है जो सभी धार्मिक और गैर-धार्मिक समुदायों को निष्पक्ष तरीके से प्रशासित कर सकती है।

धर्मनिरपेक्षता की ऐतिहासिक घटना की पृष्ठभूमि को 17वीं सदी के यूरोप में ढूंढा जा सकता है जहाँ अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च और राज्य के बीच वैमनस्य हुआ था। इससे पहले वहाँ पर 1618 से 1648 के मध्य तीस वर्ष लम्बा युद्ध हुआ था। इस तीस साल लम्बे युद्ध के परिणाम स्वरूप आठ लाख हादसे हुए। इस युद्ध में, मार्टिन लूथर कंग के नेतृत्व में व भन्न प्रोटेस्टेंट समूहों और कैथोलिक राज्यवाद-ववाद, शोषण और अमानवीयता में शामिल थे। लड़ाई तब प्रारम्भ हुई जब नव निर्वाचित महान रोमन सम्राट, फर्डिनांड II ने धार्मिक समरूपता को अपने शासन पर थोपा जो अपने लोगों को रोमन कैथोलिकवाद के लिए मजबूर करने का कार्य था। दूसरी ओर, अपने अधिकारों के उल्लंघन के कारण उत्तरी प्रोटेस्टेंट राज्य नाराज थे, जो अधिकार उनको ऑग्सबर्ग की शान्ति संधि में प्रदान किये गए थे। फर्डिनांड II के द्वारा ऐसे कार्यों ने उन्हें प्रोटेस्टेंट संघ बनाने से भी प्रतिबंधित कर दिया था। अपने पूर्वज रूडोल्फ II की तुलना में फर्डिनांड II एक धर्मनिष्ठ रोमन कैथोलिक और अपेक्षाकृत असहिष्णु था। वह अपनी कैथोलिक समर्थक नीतियों के लिए जाना जाता था।

यह युद्ध '30 वर्षों का युद्ध' या 'संप्रदायिक युद्ध' के नाम से जाना जाता है जो वेस्टफे लिया की संधि के साथ खत्म हुआ था। यह संधि परस्पर वरोधी पक्षों द्वारा अपने हितों की संतुष्टि के साथ एक

समझौता है जिसे झगड़े का निपटारा होने तक की गई व्यवस्था कहा जाता है। धीरे-धीरे, झगड़े का निपटारा होने तक की यह व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था के सद्धान्त के रूप में विकसित हो गई (हॉब्स, लॉक आदि लेखों को देखें) और राजनीतिक वर्गों के बीच इसका प्रसार हो गया। इस समय पर, धर्मनिरपेक्षता का सद्धान्त आया जिसने राज्य और चर्च को अलग-अलग कर दिया ।

धर्मनिरपेक्षता की समाजशास्त्रीय समझ अधिक सामान्य और व्यापक समझ की हकदार है। धर्मनिरपेक्षता में धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति, न्याय, स्वास्थ्य, परिवार इत्यादि के ऊपर नियंत्रण की अपनी परम्परागत सत्ता को खो देता है । 1851 में, सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में प्रगति के एक वैचारिक गठन के तहत धर्मनिरपेक्षता ने एक तर्कसंगत आंदोलन का नेतृत्व किया। पीटर बर्जर, वचार रखते हैं क धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य उस प्रगति से है जिसमें समाज का एक भाग और संस्कृति धार्मिक संस्थानों के वर्चस्व से दूर हट जाते हैं ।

सामान्यतः, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की एक व्यवस्था से है जो पूजा (उपासना) और धार्मिक विश्वास के सभी स्वरूपों को नकारती है। यूरोप में धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति 'उस सद्धान्त को परिभाषित कर रही थी जिसमें धार्मिक मान्यताओं की परवाह किए बिना, वर्तमान जीवन में नैतिकता मनुष्य के कल्याण पर आधारित होनी चाहिए । भारतीय राज्य ने अपनी नीति में परिभाषित किया क भारत 'धर्मनिरपेक्षता' का तात्पर्य धार्मिक निष्पक्षता बनाये रखना है। महात्मा गाँधी और मौलाना आजाद का धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य सर्वधर्म सद्भावना अर्थात् 'सभी धर्मों के प्रति सद्भावना' है ।

भारतीय समाज और धर्मनिरपेक्षता

भारतीय समाज एक बहु- सांस्कृतिक समाज का गठन करता है जहाँ जाति, वर्ग, धर्म, नृजातीयता और लिंग से संबंधित सामाजिक समूहों की विविध श्रेणी कानून के समक्ष समान नागरिकों की तरह एक साथ आती है। यह विविधता में एकता कहलाती है। सभी धार्मिक और नृजातीय समुदाय बिना किसी दूसरे धार्मिक या नृजातीय समूह के हस्तक्षेप के अपने अनुष्ठानों और सामाजिक प्रथाओं का पालन करते हैं । सामाजिक अन्तः क्रिया और सामान्य भाईचारे के द्वारा सामाजिक एकीकरण तथा एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के प्रति सम्मान भारतीय धर्मनिरपेक्ष संरचना में मुख्य तत्व है ।

भारत का धार्मिक बहुलवाद एक अनोखी सामाजिक संरचना रखता है। बहुलवाद एकजुटता की भावना के साथ इसके सार्वभौमिक भाईचारे, प्रेम और शान्ति को बनाए रखता है। आधुनिक समय में, बहुलवाद ज्ञान की वैज्ञानिक समझ पर आधारित सद्धांतों के एक निकाय की स्थापना के साथ आधुनिक तार्किक व्यवहार के वशाल सद्धांत / वचारधारा का भाग है। इसी प्रकार, आधुनिक राष्ट्र राज्य भी यह तार्किक वैज्ञानिक समाज को स्थापित करने का प्रयास करते हैं जहाँ धार्मिक क्रूरता, प्रजातीय हिंसा और लिंग भेद चंता के एक महत्वपूर्ण वषय बन गये हैं। वैश्विक आर्थिक क्रयाओं ने भी एक वैश्विक समाज उत्पन्न कर दिया है जिसे 'वैश्विक गाँव' कहते हैं। आर्थिक क्रयाएँ तथा व्यापार संबंध वहाँ तक सत होते हैं जहाँ व भन्न राष्ट्रों, व भन्न धर्मों, व भन्न प्रजातियों तथा लंगों के लोग वैश्विक सांस्कृतिक वनिमय की व्यवस्था में संलग्न रहते हैं। इन क्रयाओं के माध्यम से समाज व वध धार्मिक गति व धर्यों को सहन करने के साथ संवृत व्यवस्था से मुक्त व्यवस्था में परिवर्तित हो गया है।

आजादी के बाद भारत में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना को राष्ट्र निर्माण पर उत्तर- औपनिवेशिक बहस के आधार पर जाना जा सकता है। सभी धार्मिक समूहों को एक ही मंच पर लाना और वभाजन के दौरान सामूहिक हिंसा के बाद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य के रूप में घोषित करना भारतीय नेताओं के लए एक बहुत ही तनावपूर्ण परिस्थिति थी। हिन्दू- मुस्लिम संघर्षों और धार्मिक क रवाद के साम्प्रदायिक वचार के कारण देश के हर कोने में हिंसा का जोरदार प्रदर्शन हुआ। इसने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक मुस्लिम राज्य, जो पाकस्तान कहलाया, के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई, दूसरी ओर हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र ने धर्मनिरपेक्ष राज्य का गठन किया जिसका नाम भारत (इण्डिया) रखा गया। भारत ने एक आधुनिक राष्ट्र राज्य बनाने के लए सभी धार्मिक समूहों को एक ही मंच पर लाने के लए अपने आधाभूत सद्धांत के रूप में धर्मनिरपेक्षता की आधुनिक पहचान को ग्रहण किया। इसने हिन्दू बाहुल्य प्रांतों के अंदर महत्त्व सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता की ओर अग्रसर किया तथा सभी धार्मिक समुदायों जैसे हिन्दू, मुस्लिम, इसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी व जो लोग धर्म को नहीं मानते उनके मध्य भी आपसी सहयोग स्थापित किया

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में धर्मनिरपेक्षता की ऐतिहासिक समझ भारतीय पुनर्जागरण की अवधि में निहित है। इसका तात्पर्य धार्मिक वश्वास में कलंक और सामाजिक बुराईयों के वरुद्ध सुधार आंदोलनों के समय

से है। राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र वदयासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि जैसे कुछ सामाजिक सुधारकों ने सामाजिक बुराईयों और हिन्दू धर्म में संकीर्ण मान सकता के वरुद्ध संगठित होकर काम किया। उनके तार्किक वचारों और आधुनिक सोच का समाज में गहरा असर है।

औपनिवेशिक प्रशासन भारत के संपूर्ण समाज में एक वृहत (वशाल) परिवर्तन लेकर आया था। ब्रिटिश प्रशासन के अंदर जातिगत संरचना के सामंती वर्चस्व, धार्मिक घृणा, नारी के दमन आदि पर प्रश्न चह्न लगाये गये। औपनिवेशिक प्रशासन के अन्तिम चरण के दौरान, भारतीय समाज व्यापार, उद्योगों, शहरी जीवन और आधुनिक शिक्षा (गैर-धार्मिक शिक्षा) की वृद्धि के कारण आधुनिक हो गया जिसने समाज में तार्किकता के बढ़ावे और धर्मनिरपेक्षता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक प्रशासन ने अपनी व्यापार गति व धर्मों को क्षेत्रीय और धार्मिक सीमाओं से आगे वस्तुतः भी किया जिसने धर्मनिरपेक्ष समझ के लिए एक वातावरण तैयार किया। अखबारों, पत्रिकाओं, वाद-ववादों और नागरिक समाज ने समानता, सम्मान (गौरव), व्यक्तिगत अधिकारों तथा स्वतन्त्रता की समाज के सभी भागों के लिए माँग की और व भन्न स्तरों पर सार्वजनिक वर्मश का हिस्सा बना।

उद्देश्य

1. धर्मनिरपेक्षता के अर्थ और वचार को अध्ययन
2. धर्मनिरपेक्षता के सामाजिक संदर्भ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करने में
3. धर्मनिरपेक्षता की समस्याओं को समझने में

धर्मनिरपेक्षता के भीतर संघर्ष

व्यवस्था में पूर्णता प्राप्त करने के लिए व्यवस्था के अंदर संघर्ष एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान परिस्थिति में भारतीय धर्मनिरपेक्ष संरचना बढ़ते हुए धार्मिक क रवाद और धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियों के अर्थ में अधिक जटिल है। समकालीन भारत शासक वर्ग अधपत्य और राजनीतिक अभजन के द्वारा धार्मिक क रवाद की पुर्नव्याख्या के कारण व भन्न चुनौतियों को अनुभव कर रहा है, जहाँ भारतीय मध्यम वर्ग इसके राजनीतिक फायदों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

धर्म अपने राजनीतिक अधपत्य और प्रतीकात्मक पूँजी के लए भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उदाहरण के तौर पर, भारत के उत्तरी भाग में दक्षिण पंथी (Right Wings) उत्तरीपंथी राजनीति ने खास तौर से 1992 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के द्वारा बाबरी मस्जिद वध्वंस मामले में हिंदू क रपंथी समूह का नेतृत्व किया जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) का राजनीतिक अधपत्य था। ठीक इसी प्रकार, भारत के दूसरे भागों में, समकालीन राजनीति ने सत्ता को बनाए रखने के लए धर्म को आधुनिक राजनीति के एक शक्तिशाली हथियार के रूप में पुनः गढ़ दिया है। इस प्रकार की राजनीति बहुत से हिंसक परिणामों जैसे दंगों, अत्याचारों, सामूहिक हत्याओं आदि की ओर अग्रसर करती है

दूसरी ओर, धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल भी अपने राजनीतिक फायदे के लए इस प्रकार के धार्मिक क रवाद में फंस जाते हैं। इस प्रकार, एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल हुए बिना, भारतीय समाज की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संरचना अपनी धर्मनिरपेक्ष संरचना को बनाए रखने के लए बहुत सी चुनौतियों का सामना करती है। सेन (2005) ने भारतीय राजनीति में पहचान के वषय की व वधता की आलोचना की है। उन्होंने भारतीय राजनीतिक नेताओं और सक्रियावादी बौद्धक समूहों का धर्म वशेष के प्रति पक्षपात पर भी जोर दिया जो धर्मनिरपेक्षता के सही अर्थों को शथल करता है। सेन धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय बौद्धक वमर्श के प्रति बहुत आलोचनात्मक है जो धर्मनिरपेक्षता को प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीके के रूप में आधुनिकता को उजागर करता है। यह वचार पुष्ट करता है क आधुनिकता के माध्यम से परम्परागत धार्मिक क रतावाद दूर हो जायेगा।

भारतीय धर्म और धर्मनिरपेक्षता

यह पहले ही उल्लेख किया है क भारत एक बहुधार्मिक देश है जहाँ व भन्न प्रकार के धार्मिक समूह एक साथ रहते हैं। 81 प्रतिशत जनसंख्या के साथ हिन्दू धर्म सबसे अधिक आबादी वाले धार्मिक समूहों में से एक है। अपनी 13 प्रतिशत आबादी के साथ मुस्लिम दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समूह के रूप में अपना स्थान लेते हैं। इसके बाद सख, ईसाई, बौद्ध पूरे भारत में फैली एक बड़ी आबादी है।

व भन्न धर्मों की अपनी स्वयं की धार्मिक वचारधारा (सद्दांत) वश्वास व्यवस्था और अनुष्ठान प्रथाएँ हैं। इन सभी धर्मों का धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे के लए अपना दर्शन है। ये धर्मनिरपेक्ष

दर्शन धर्म और सामाजिक प्रथाओं की व वधता के अंदर एक संगठित व्यवस्था बनाए रखने के लए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ।

भारतीय समाज एक बहुधर्मी समाज है जहां पर व भन्न धर्मों का एक साथ समान रूप से महत्व पाया जाता है। ले कन धर्म व्यक्ति क लए आस्था का ऐसा वषय बन जाता है क लोग उसकों स्वयं म सम्प्रदाय क दृष्टिकोण से देखने लगते है। उसको देखने का जा नजरिया होता है क वह बहुत संकीर्ण होता जा रहा है। भारत आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही एक धर्म निरपेक्ष देष रहा है। ले कन वगत कुछ दषकों से धर्म निपेक्षता से सम्बन्धित एक ऐसी बहस चली है क जनमानस को फर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी सन्दर्भ में धर्म निरपेक्षता को परिभाषित करने से पूर्व यह स्पष्ट करना अ धक महत्वपूर्ण होगा क धर्म क्या है, क्यो क व भन्न सामाजिक वैज्ञानिकों के मतों में धर्म को लेकर व भन्नताएं देखने को मलती है। दुर्खीम (1912) धर्म को एक अनुभव सम्बन्धित कार्य मानते है जो हमें समझने के तरीके से अवगत कराता है तथा एक सामाजिक तथ्य है वहीं सामान्य अर्थ में धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य धर्म के राजनीति से पृथक्करण से है, ले कन पृथक्करण अपने आप में एक ऐसा जटिल शब्द है, जिसका भन्न- भन्न समाजों में भन्न- भन्न अर्थों मे इसका प्रयोग कया गया है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार- “धर्म निरपेक्ष वह व्यक्ति है जो केवल लौकिक बातों से सम्बन्धित हो, धर्म क मामलों से नहीं।” वहीं साम्यवादी वचारधारा पर आधारित समाज में धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य गैर धर्म क या धर्म - वरोधी प्रवृत्ति से लया जाता है। पाश्चात्य समाज के सामान्यतः यह एक ऐसे सद्दान्त के रूप प्रतिपादित कया गया है। जिसका उद्देश्य राज्य एवं गरजाघर के बीच पृथक्करण की स्पष्ट व्यवस्था स्थापित करना है अर्थात् धर्म या वश्वास को व्यक्तिगत अन्तरात्मा की सीमा बाँधते हुए सार्वजनिक कार्यों एवं नीति निर्माण से अलग की व्यवस्था की गयी क्यो क इन मामलों में राजनीति एवं राज्य के अनन्य क्षेत्राधिकार में डाल दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवधान बनने के पश्चात संदर्भ में स्पष्टता आयी, इसके अनुसार राज्य ना तो धर्म क संगठनों के क्रयाकलाप के हस्तक्षेप करेगा और ना ही गरिजाघर राज्य के क्रयाकलापों में हस्तक्षेप या दखलंदाजी करेगा, परन्तु साथ ही साथ राज्य का यह कर्तव्य भी होगा क व्यक्ति को अपनी इच्छानुरूप धर्म पालन का अधिकार प्रदान कर

पाश्चात्य समाज में धर्म एवं राजनीति का जो पृथक्करण प्रचलित हुआ वह भारत में संभव प्रतीत नहीं होता क्यो क आधुनिक भारतीय सभ्यता तत्कालीन पाश्चात्य सभ्यता से भन्न है जब वहाँ धर्म निरपेक्षता का सद्दान्त प्रतिपादित हुआ था। अतः भारत में धर्म निरपेक्षता राज्य के आधार के रूप में

पृथक्करण के पश्चिमी सद्धान्त का पुर्नमूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि यहाँ की व भन्न स्थितियाँ अपनी व शष्ट कठिनाइयों के साथ रचनात्मक दृष्टिकोण की माँग करती है। भारत में धर्म निरपेक्षता की माँग है क राजनीति व धर्म के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध ना, क्योंकि ऐसा सामान्यतः सांप्रदायिक राजनीति के दिखता है। यही कारण है क धर्म निरपेक्षता के प्रति भारतीय दृष्टिकोण सर्वधर्म समभाव का रहा है

धर्म निरपेक्षता पर अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दृष्टिकोण

अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो धर्म निरपेक्ष के प्रश्न पर बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक के वचार परस्पर वरोधी परिलक्षित होते हैं, जहाँ बहुसंख्यक इसे अल्पसंख्यकों के प्रति तुष्टीकरण की नीति मानते हैं, वहीं अल्पसंख्यक इसे छलवापूर्ण धर्म निरपेक्षता के रूप स्वीकार करते हैं, उनका मानना है क यह उनके अधिकारों का संरक्षण करता है। वस्तुतः धर्म निरपेक्षता के सद्धान्त की सकारात्मक व्याख्या तथा क्रयान्वयन नहीं होने के कारण इसकी निहित स्वार्थ के आधार पर आलोचना की जाती रही है। ऐसा होने से एक तरफ तो सम्प्रदायवाद को बढ़ावा मलता है वहीं दूसरी तरफ भारतीय धर्म निरपेक्षता पर भी निरंतर खतरे में बादल मंडराते नजर आते हैं। इस सन्दर्भ में राजीव मार्गव कहते हैं क धर्म निरपेक्षता के भारतीय स्वरूप में पृथक्करण का सद्धान्त धर्म और राजनीति के बीच एक सैद्धान्तिक दूरी के रूप में समझा जाना चाहिए। यहाँ सद्धान्त की दूरी को राजनीति की धर्म में स्वतंत्रता के रूप में देखने की आवश्यकता है, ना क इसके प्रतिमूल रूप में अर्थात् राज्य के क्रया कलाप, राजनीतिक नीति तथा नीति प्राथमिकताएँ धर्म की दखलंदाजी से स्वतंत्र है, परन्तु राज्य को धर्म क सुधार हेतु हस्तक्षेप का अधिकार भी प्राप्त है जिसका निर्धारण गम्भीर मुद्दों के आधार पर तथा ववेक सम्मत आधार पर हाना होगा। इतना ही नहीं सभी वश्वास (प्रथाएँ) भले ही धर्म द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो, जैसे क अस्पृश्यता, जाति-भेद, बहु-ववाह, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का बहिष्कार तत्काल अवैद्य घोषित करनी होगी। ऐसा इस लये आवश्यक होगा क्योंकि यह संवधान की उस नियामक व्यवस्था के लये अहितकारी है, जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रबल जनता की भागेदारी के माध्यम से अंतर्ग्रस्त मूल्यों के सामांजस्य पर आधारित है। पार्ट चर्जी(1997) के वचार में जब राज्य धर्म-सुधार जैसे कानून बनाता है तो राजनैतिक नेतृत्व द्वारा राज्य व धर्म के वभाजन का अतिक्रमण या शोषण जैसा प्रतीत होता है।

निष्कर्ष

आजादी के बाद से, भारत ने एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है जहाँ सभी धार्मिक समुदायों को उनके अपने धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का अनुसरण करने की स्वतंत्रता है। संप्रदायिक तनावों को सुलझाने और अपने उदार दृष्टिकोण के द्वारा शान्ति स्थापित करने में शासक वर्ग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिक समाजों और प्रशासनिक संगठनों ने सामुदायिक सामंजस्य बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष राजनीति ने एक धर्मनिरपेक्ष समाज के पुनर्गठन के लिए पूरक समर्थन दिया है।

संदर्भ

1. भार्गव आर. एवं आचार्य ए.(2011) राजनीतिक सद्धान्त एक परिचय, पीयरसन पब्लिकेशन, दिल्ली, पेज 285-286
2. भार्गव आर. (1997) सेकुलरिज्म एंड इट्स क्रटीक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस दिल्ली।
3. चटर्जी पी.(1997) स्टेट एण्ड पा लटिक्स इन इण्डिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. दुर्खी म ई. (1912) द एलीमेन्ट फार्म आफ रिलीजियस लाईफ, लन्दन: जार्ज एलेन एवं अन वन ल मटेड।
5. गांधी एम. के. (2009) सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पाम लीफ प्रेस।
6. आक्सफोर्ड एडवांस्ट लर्निंग डक्शनरी ऑफ करेन्ट इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, 1997.
7. सईद एम.एम.(2011), भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत बुक सेन्टर पब्लिकेशन, लखनऊ, पेज-404-411
8. सन्हा मनोज (2012) समकालीन भारत एक परिचय, ओरिण्ट ब्लैकस्वॉन पब्लिकेशन, पेज-297
9. श्रीनिवास एम.एन (1965) सोशल चेंज इन मार्टिन इण्डिया, यूनिवर्सिटी कैलीफोर्निया प्रेस।
10. वेबर मैक्स (1963) द सो शयोलॉजी ऑफ रिलीजन, बेअकान प्रेस